

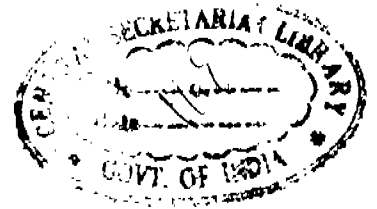


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 51]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1996/फाल्गुन 9, 1917

No. 51]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1996/PHALGUNA 9, 1917

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बजट अनुभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1996

फा.सं. 15(59)-बी (डी)/95-निम्नलिखित को
सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता
है :—

बजट 1996-97

(अन्तर्गम)

वित्त मंत्री

श्री मन मोहन सिंह

या

भाषण

28 फरवरी, 1996

अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 1996-97 का अन्तर्गम बजट प्रस्तुत करने
के लिये उपस्थित हूँ।

2. पांच वर्ष पूर्व भारत की जनता ने प्रधान मंत्री
श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के उत्साहवर्धक एवं दूरदर्शितापूर्ण
नेतृत्व में हमारी पार्टी को शासनादेश दिया था। हमने
ऐसे समय में कार्यभार संभाला था जब अर्थव्यवस्था
लड़खड़ा रही थी। मुद्रास्फीति नियंत्रण के बाहर थी,
निर्यातों में कमी हो रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार कम
होकर मुश्किल से दो सप्ताह की अवधि के आयातों के
बराबर रह गये थे तथा उद्योग वस्तुतः चरमरा गये थे।
हमें स्थूल आर्थिक स्थिरता को पुनःस्थापित करने के
लिये और फिर यथा-संभव शीघ्र ही अर्थव्यवस्था को
तीव्र एवं साम्यिक आर्थिक प्रगति के पथ पर वापस लाने
के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ी।

3. इसके लिये जिस नीति का हमने अनुसरण किया है,
उसका प्रधान मंत्री ने स्वयं कई अवसरों पर इस सदन के
समक्ष उल्लेख किया है। हमारा यह प्रयास रहा है कि
हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़े और उसका व्यापक
विकास हो जिसकी वजह से ही हमारे सभी लोगों के
बढ़ते हुए जीवन स्तर को कायम रखा जा सकता है। हमने
अपनी अर्थ-व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने, उत्पादकता
में सुधार लाने तथा सभी क्षेत्रों में कार्यक्षमता को बढ़ाने
का प्रयास किया है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था का

विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक कारगर ढंग से समा-मेलन करने का प्रयास किया है ताकि हम विश्व-बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें और साथ ही अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निवेश को आकृष्ट कर सकें जैसा कि एशिया के अन्य बहुत से देशों ने अपने लाभ के लिये किया है। सबसे अधिक हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस प्रक्रिया में हमारे समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों की जरूरतों का लगातार ध्यान रखा जाए। क्योंकि निजी क्षेत्र का ऐसे बहुत से क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ है जो कि पहले राज्य के लिये आरक्षित थे अतः राज्य की गतिविधि का आकर्षण तथा सरकारी संसाधनों का नियोजन अब गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर संकेन्द्रित किया जा रहा है जहां अकेले बाजार अर्थव्यवस्था तेजी से लाभ प्रदान नहीं कर सकती है।

4. विगत पांच वर्षों की यात्रा कठिन और लाभप्रद दोनों ही प्रकार की रही है। मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने जो भी चाहा वह सब पा लिया है। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी विचारधारा और आकांक्षाओं की भलीभांति पुष्टि करते हैं। अब मैं संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करूंगा।

5. मुद्रास्फीति हमारी सबसे प्रबल शत्रु है और इससे किसी अन्य की अपेक्षा गरीबों को अधिक क्षति पहुंचती है। इसलिये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हमारी प्रथम प्राथमिकता थी। राजकोषीय घाटे को कम करके, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित करके और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाकर हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कठिन परिश्रम किया। परिणाम सुस्पष्ट है। अगस्त, 1991 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 17 प्रतिशत के अधिकतम स्तर पर थी। इसे फरवरी, 1996 में 5 प्रतिशत से नीचे लाया गया है जो 1988 से लेकर अब तक निम्नतम स्तर पर है। इसके अतिरिक्त, गेहूं, खाद्य तेलों और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की वार्षिक मूल्य वृद्धि दर और भी कम है। गरीब वर्गों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिये, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। इस सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) का विस्तार जनजातीय, पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में 1775 विकास खण्डों तक किया गया है। 650 से भी अधिक और विकास खण्डों में इस सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स.सा.वि.प्र.) के विस्तार का कार्य चल रहा है।

6. हमारी नीतियों से आर्थिक वृद्धि का पुनर्स्थान भी हुआ है। 1991-92 के संकटकालीन वर्ष में एक प्रतिशत से भी कम की मन्दी के उपरान्त, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1992-93 तथा 1993-94 दोनों

वर्षों में बढ़कर 5 प्रतिशत वार्षिक पर आ गई, फिर 1994-95 में यह बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई और 1995-96 के लिये 6.2 प्रतिशत की निरन्तर उच्च वृद्धि होने का अनुमान है। किसी भी रूप में यह सम्बन्ध विश्व में गंभीर स्थूल आर्थिक संकट से उभरने वाली एक सबसे तीव्र एवं सबसे मजबूत उपलब्धि रही है। आठवी योजना के पहले चार वर्षों में वृद्धि औसतन 5.7 प्रतिशत रही है। यह 5.6 प्रतिशत के योजना लक्ष्य के अनुरूप है।

7. इस असाधारण उपलब्धि को अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों से अच्छे कार्य-निष्पादन से संबल प्राप्त हुआ है। कृषि में हमारी दो-तिहाई जनता को आजीविका प्राप्त होती है और हमारी नीतियों में इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। हमने लाभकारी मूल्य प्रदान किये हैं। हमने कृषि वस्तुओं में आन्तरिक और विदेशी व्यापार बाधाओं को समाप्त कर दिया है। हमने कृषि-प्रसंस्करण वाले क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया है। हमने अपनी विदेश व्यापार नीतियों में कृषि के प्रति पूर्वाग्रह को अत्यधिक अनुकूल बना दिया है। इसका उद्देश्य हमारे किसानों को शीघ्र आय अर्जन के अवसर उपलब्ध कराना रहा है।

8. मुझे मालूम है कि माननीय सदस्य किसानों की यथोचित प्रशंसा करने में मेरा साथ देंगे। इन नई नीतियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यधिक अनुकूल रहा है। वर्ष 1991-92 के संकट के दौरान कृषि उत्पादन में गिरावट आई लेकिन उसके पश्चात् अगले तीन वर्षों में औसतन प्रति वर्ष 4 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। खाद्य उत्पादन में भी औसतन प्रति वर्ष 4 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई जिससे वर्ष 1994-95 में यह 191 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 1995-96 में इसी तरह भरपूर उत्पादन होने की आशा है। तथापि खाद्यान्न उत्पादन तो हम कहानी का केवल एक अंश है। कृषि में भी विविधता लाई गई है। दुग्ध उत्पादन में 1990-91 तथा 1994-95 के बीच लगभग 10 लाख टन तक की वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है।

9. उन आलोचकों, जो यह दावा करते थे कि हमारी नीतियों में कृषि की उपेक्षा की गई है, में बस इतना ही कहना काफी है।

10. हमारे उद्योग ने निर्मुक्त घरेलू उद्योग की हमारी नीतियों के प्रोत्साहन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का शानदार ढंग से प्रत्युत्तर दिया है। बहुतों का यह पूर्वानुमान था कि आयातों के उदारीकरण से घरेलू उद्योग समाप्त हो जाएगा। अपने उद्योग पर हमें अधिक विश्वास था। पांच वर्ष पहले, मैंने कहा था कि "हमारे उद्योगी किसी से कम नहीं हैं।" हमने उनमें जो विश्वास

जताया था उसकी उन्होंने भलीभांति पुष्टि कर दी है। 1991-92 में औद्योगिक उत्पादन अवरुद्ध था। यह तेजी से और सुधर कर 1993-94 में 6 प्रतिशत तक बढ़ गया और फिर 1994-95 में यह बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया। औद्योगिक वृद्धि 1995-96 की प्रथम छमाही में और बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 1994 में बढ़कर 25 प्रतिशत तक हो गया। यह बुनियादी वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की अन्य विस्तृत श्रेणियों में दर्ज की गई वृद्धि के दुगुने में भी अधिक है। 1995-96 की प्रथम छमाही में पूंजीगत वस्तुओं का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से आगे बना रहा जिसमें 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आयातों की प्रतिस्पर्धा में अर्थ व्यवस्था का मार्ग खुल जाने के बावजूद ऐसा हुआ है। अब कोई भी हमारे उद्योग के अन्तर्निहित सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धात्मकता पर सन्देह नहीं कर सकता।

11. मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए विशेष रूप से प्रसन्न हूँ कि हमारी सुधार नीतियों ने लघु उद्योग को विशेष बल मिला है। संकट के बाद प्रत्येक वर्ष, लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन में समग्र औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये, 1993-94 में लघु उद्योग उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हो गई जबकि समग्र औद्योगिक उत्पादन में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह 1994-95 में लघु उद्योग की वृद्धि 10.1 प्रतिशत थी जोकि 8.6 प्रतिशत की समग्र औद्योगिक वृद्धि से अधिक थी।

12. जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, सुधार की हमारी नीति में गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। हमने तीव्र, व्यापक आधार वाले, रोजगार-सृजनकारी विकास को बढ़ावा देने, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिये विशेष कार्यक्रमों का विस्तार एवं प्रसार करने और सामाजिक क्षेत्रों तथा सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने का त्रिपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है। 1991 में हमारे आलोचकों ने यह चेतावनी दी थी कि आर्थिक सुधारों के कारण वेशुमार बेरोजगारी बढ़ेगी तथा करीबों को समर्जन का सामना करना पड़ेगा। इन परिणामों से ये आशंकाएँ दूर हो गई हैं।

1991-92 में अर्थ-व्यवस्था में रोजगार की कुल वृद्धि 3 मिलियन थी। अगले दो वर्षों में यह दुगुनी होकर औसतन 6 मिलियन हो गई तथा 1994-95 में यह 7 मिलियन से भी अधिक हो गई। रोजगार में वृद्धि इस साल और भी अधिक होने की संभावना है। यह अस्सी के दशक में प्रति वर्ष 5 मिलियन से कम की औसत वृद्धि के बराबर है।

योजना आयोग के निर्धनता संबंधी अद्यतन अनुमान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में महत्वपूर्ण कमी दर्शाते हैं। यह अनुपात 1987-88 के 25 प्रतिशत से भी अधिक से कम होकर 1993-94 में 19 प्रतिशत से नीचे आ गया।

हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग अकुशल कृषि श्रमिक की वास्तविक मजदूरी में भी सुधार हुआ है। 1991-92 के संकटकालीन वर्ष में वास्तविक मजदूरी में 6 प्रतिशत तक की गिरावट आयी। उसके उपरान्त उसमें अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष निरन्तर 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

13. कड़े राजकोपीय प्रतिबंधों के बावजूद, 1992-93 और 1995-96 के मध्य के तीन वर्षों में हमने केन्द्रीय आयोजना के बजट आबंटन को बढ़ाकर ग्रामीण विकास के लिये लगभग 150 प्रतिशत तक, शिक्षा के लिये 90 प्रतिशत से अधिक, प्राथमिक शिक्षा के लिये लगभग 130 प्रतिशत तक तथा स्वास्थ्य के लिये 120 प्रतिशत से भी अधिक कर दिया है। हमने कमजोर वर्गों के लिये महत्वपूर्ण नये कार्यक्रमों एवं योजनाओं की शुरुआत की है।

रोजगार आश्वासन योजना मंड़ी के समय में देश के सबसे गरीब 3175 विकास खण्डों में प्रति परिवार दो व्यक्तियों की दर से अकुशल ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को 100 दिनों के लिये सुनिश्चित रोजगार प्रदान करती है।

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार-द्वारा छोटे-छोटे उद्यमों की स्थापना करके रोजगार सृजन के लिये तैयार की गई है। वर्ष 1994-95 में इस योजना के अधीन 1.9 लाख लाभभोगियों को ऋण दिये गये थे। वर्ष, 1995-96 के लिए 2.6 लाख लाभभोगियों का लक्ष्य रखा गया है।

—राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तीन मुख्य घटक हैं, पहले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वृद्धों को केन्द्रीय सरकार से 75 रुपए की मासिक वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। इसमें 54 लाख लोगों के लाभान्वित होने की आशा है। दूसरे, गरीब परिवारों के प्रमुख आय अर्जक की मृत्यु होने पर दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले में 10,000 रुपए तथा प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने के मामले में 5,000 रुपए के एकमुश्त उत्तरजीवी लाभ की व्यवस्था है। इससे प्रतिवर्ष 4.5 लाख परिवारों के लाभान्वित होने की आशा है। तीसरे, गर्भवती माताओं के लिए 300 रुपए के मातृत्व लाभ की व्यवस्था है। इससे प्रतिवर्ष 46 लाख महिलाओं के लाभान्वित होने की प्रत्याशा है।

—मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य 3 वर्षों में पहली से चौथी कक्षाओं के 11 करोड़ बच्चों के पोषाहार और विद्यालय में उपस्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के पहले वर्ष 3.4 करोड़ बच्चों को पहले ही इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

—इन्दिरा आवास योजना के अधीन वर्ष 1994-95 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के लिए 4 लाख मकान बनाए गए थे। इस योजना के अधीन वर्ष 1995-96 में 10 लाख मकान बनाए जाएंगे।

—महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य घरेलू बचतों पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण प्रदान करके महिलाओं को समर्थ बनाना है।

—‘नाबार्ड’ में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि स्थापित की गई है। यह मध्यम और लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और अन्य ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं की चालू परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी।

—1000 करोड़ रुपए की एक विशेष बैंक संघीय निधि की व्यवस्था से ग्राम और खादी उद्योगों के लिए बैंक का विस्तार किया जा रहा है।

—गरीब परिवारों के लिए कम प्रीमियम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रुपए का जीवन कवच प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम की एक नई समूह जीवन बीमा योजना।

—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, जिसे हमने 1992 में स्थापित किया था, ने लाभभोगियों को 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं।

—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त और विकास निगम ने 400 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किये हैं।

—अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सहायता देने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

—400 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी सहित विकलांग विकास और वित्त निगम की स्थापना की जा रही है।

14. हमें औद्योगिक विकास की गति तेज करने में भारतीय श्रमिकों द्वारा निभाई गई भूमिका पर गर्व है। उनके हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई उपाय किए गए हैं। हमने वोनस-भुगतान की पात्रता सीमा 2500 रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह और वोनस-परिकलन की सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर

दी है। इसके पूर्व, सरकार ने श्रमिकों को 1 लाख रुपए तक उपदान प्राप्त कर सकने के लिए उपदान-भुगतान अधिनियम के अधीन सीमा बढ़ा दी थी। वोनस पात्रता और वोनस परिकलन की संशोधित सीमा गैर-सरकारी और सरकारी कर्मचारियों दोनों पर लागू है। यहां तक कि हमने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन से पूर्व ही सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की एक किस्त प्रदान कर दी। तत्पश्चात् दूसरी किस्त वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दे दी गई। अंतरिम राहत पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को भी प्रदान की गई है। हमने उपदान के परिकलन के लिए महंगाई भत्ते के एक भाग को भी वेतन के साथ विलयित कर दिया है।

15. संविधान (निहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 का पारित होना एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायत की स्थापना करना एक संवैधानिक आवश्यकता बना दिया। यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को पंचायतों में अनिवार्यतः पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह समाज के इन अल्पाधिकार-प्राप्त वर्गों को शक्ति प्रदान करने के लिए एक मुख्य कदम है। इस शक्ति की सुपुर्दगी को वास्तविकता बनाने के लिए प्रत्येक राज्य को उन मिश्रितताओं, जिनमें राज्य और पंचायतों के बीच राज्य राजस्व का वितरण नियंत्रित करना चाहिए, की सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग गठित करना अपेक्षित है। दसवें वित्त आयोग ने भी आगामी चार वर्षों की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने के लिए लगभग 4,400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।

16. वर्ष 1991 का संकट हमारे भुगतान संतुलन में स्पष्टतया प्रदर्शित किया गया था। पिछले पांच वर्षों में हमारे विदेशी व्यापार और विदेशी भुगतान नीतियों ने हमारी कमजोरियों को मजबूती में बदल दिया है:

— निर्यातों में वर्ष 1991-92 में डालर मूल्य में गिरावट आई। उनमें वर्ष 1993-94 में 20 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात वृद्धि में वर्ष 1995-96 के प्रथम 9 महीनों में 24 प्रतिशत की तेजी आई।

—व्यापार संबंधी उदारीकरण ने वास्तविक रूप से विदेश व्यापार में हमारी आत्म-निर्भरता में वृद्धि की है। आयात भुगतानों की तुलना में निर्यात आय का अनुपात अस्सी के दशक में औसतन 60 प्रतिशत से बढ़कर पिछले दो वर्षों में 90 प्रतिशत हो गया है।

—विदेशी निवेश वर्ष 1991-92 में 200 मिलियन डालर से भी कम से बढ़कर पिछले वर्ष लगभग 5 बिलियन डालर हो गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के इस

वर्ष बढ़कर लगभग 2 बिलियन डॉलर हो जाने की आशा है। माननीय सदस्यों को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि 85 प्रतिशत से भी अधिक विदेशी निवेश संबंधी अनुमोदन आधारभूत संरचना सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में हैं और 80 प्रतिशत से भी अधिक प्रस्तावों में भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम शामिल हैं।

—वर्ष 1991 के संकट के समय हमारा विदेशी ऋण प्रति वर्ष 8 बिलियन डॉलर की दर से बढ़ रहा था। अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1995 तक भाड़े चार वर्षों में विदेशी ऋण की वृद्धि प्रतिवर्ष औसतन केवल 2.2 बिलियन डॉलर थी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, विदेशी ऋण वर्ष 1991-92 में 41 प्रतिशत के शीर्ष से घटकर सितम्बर, 1995 में लगभग 29 प्रतिशत हो गया। तदनुसार ही, वर्तमान आय के प्रतिशत रूप में ऋण शोधन भुगतान के वर्ष 1990-91 में 35 प्रतिशत से भी अधिक से घटकर वर्ष 1995-96 में 27 प्रतिशत से भी कम हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक विदेशी ऋण का समानुपात भी मार्च, 1991 में 10 प्रतिशत से भी कम करके सितम्बर, 1995 में 5 प्रतिशत से भी कम पर लाया गया है।

17. आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में, हमने अपनी बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रचालन हानि घोषित करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या वर्ष 1992-93 में अप्रत्याशित रूप से 8 से घटकर वर्ष 1994-95 में केवल एक हो गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पात आस्तियों का औसत अनुपात भी वर्ष 1992-93 में 26 प्रतिशत से काफी घटकर वर्ष 1994-95 में 20 प्रतिशत हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वास और पुनर्गठन का एक वृहत कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

18. पूंजी बाजार सुधार के हमारे कार्यक्रम ने मुख्य निर्गमों के माध्यम से निवेश योग्य निधियों के संग्रहण में अत्यधिक वृद्धि की है जो कि वर्ष 1991-92 में लगभग 6000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 27,505 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपने स्टॉक एक्सचेंज की सुस्पष्टता, क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार करने की दृष्टि से पूंजी बाजारों पर विनियमन और पर्यवेक्षण सुदृढ़ किया है। पूंजी बाजारों की आधारभूत संरचना और कार्यशैली को आधुनिक बनाने के लिए सुव्यवस्थित और दृढ़ प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1992 में मैं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मौजूद नहीं था। वर्ष 1995 तक हम आधुनिक, कम्प्यूटरीकृत और अनुवीक्षण-आधारित एक्सचेंज, जिसने व्यापार में सुस्पष्टता के नए मानक स्थापित किए, का देश में अन्य किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की तुलना में व्यापार

में अधिक हिस्सा था। हमने निक्षेपागार की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के भी उपाय किए हैं, जो हमारी निपटान प्रणाली में काफी सुधार लाएगी।

19. वित्तीय क्षेत्र में हमारे सुधारों को हमारी अर्थ-व्यवस्था में बचतों और निवेशों के संवर्धन के लिए तैयार किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा है, हमें विकास प्रक्रिया के वित्तपोषण के लिए अधिक से अधिक अपने स्वयं के संसाधनों पर ही निर्भर रहना चाहिए। मुझे इस माननीय सदन को सूचित करने हुए प्रसन्नता हो रही है कि आत्म-निर्भरता पर बल दिए जाने के हमारे प्रयासों को सफलता मिली है। पिछले वर्ष हमारी सकल घरेलू बचतों की दर (स.घ.उ. के अनुपात के रूप में) ने 24.4 प्रतिशत का नया रिकार्ड स्थापित किया, जो हमारे इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक है। हमने सकल घरेलू उत्पाद के 25.2 प्रतिशत के रूप में उच्च दर के सकल घरेलू निवेश का वित्तपोषण किया और सकल घरेलू उत्पाद के 22.2 प्रतिशत पर वार्षिक सकल नियत निवेश के रिकार्ड उच्च स्तर का समर्थन प्रदान किया।

20. अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में, आज हमारी अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत से भी अधिक की दर से वृद्धि हो रही है। उद्योग में तेजी से विकास हो रहा है। कृषि उत्पादन बहुत अच्छा है। खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार हैं। रोजगार वृद्धि उत्साहवर्धक है। निर्धनता कम हो रही है। मुद्रास्फीति कई वर्षों से सबसे कम स्तर पर है। निर्यातों में भरपूर वृद्धि हो रही है। विदेशी निवेश की स्थिति काफी अच्छी है। विदेशी मुद्रा प्रार्थित भंडार की स्थिति काफी अच्छी है और बचतों तथा निवेश का स्तर भी अधिक है।

21. ये सभी प्रभावशाली आर्थिक उपलब्धियां हैं। वे हमारी नीतियों में एक क्रमिक विकास लाने में प्रधान मंत्री के राजनीतिक नेतृत्व और दूरदर्ष्टि के प्रत्यक्ष परिणाम हैं, जिन्होंने हमारे श्रमिकों और किसानों, हमारे उद्यमियों और हमारे प्रबंधकों, हमारे वैज्ञानिकों और अन्य व्यावसायिकविदों को उनकी अल्लोहित कार्यक्षमता प्रदर्शित करने के योग्य बनाया है। प्रवर्तित गतिशीलता अच्छे भविष्य का आभास प्रदान करती है। परंतु फिर भी, आर्थिक सुधारों का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। चुनावों के बाद चाहे जो भी सरकार सत्ता में आए उसे पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक निष्पादन के मजबूत रिकार्ड का बनाए रखने और उसमें सुधारने की चुनौती का सामना करना होगा। यह कार्य सरल नहीं होगा। मुद्रास्फीति को कम रखने, ब्याज दरें घटाने और भुगतान संतुलन पर दबाव रोकने के लिए राजकोषीय घाटे और कमी लाना अनिवार्य होगा। हमने विद्युत्, दूरसंचार, पेट्रोलियम, सड़कों तथा पत्तनों जैसे मुख्य आधारभूत क्षेत्रों में निजी निवेश शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्युत् तथा दूरसंचार क्षेत्रों में की गई हमारी पहल को जबरदस्त बढ़ावा मिला है तथा सड़कों, पुलों और पत्तनों के क्षेत्र में निजी निवेश की शुरुआत

हो चुकी है। परन्तु हमें अपनी इस पहल को जारी रखना होगा और मुख्य आधारभूत संरचना क्षेत्रों के लिए नीति संबंधी ढांचे में और सुधार करने होंगे ताकि सरकारी और निजी निवेश का उच्च स्तर, पर्याप्त आपूर्तियों में सक्षम प्रचालन और विश्वसनीय सेवाओं की विस्तारित व्यवस्था और समर्थन कीमतों को सुनिश्चित बनाए रखा जा सके। अगर आर्थिक वृद्धि रोजगार और नियातों में मौजूदा उल्हासजनक स्थिति बनाए रखनी है तो विद्युत्, कोयला, पेट्रोलियम, सड़कों और पत्तनों के क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सुधारों को जारी रखना होगा। व्यापार और औद्योगिक नीति में और सुधार करना आवश्यक है। सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन और सुधार उल्हासपूर्वक करना होगा। हमारी औद्योगिक संबंधी प्रणाली में भी सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे सामाजिक क्षेत्रों, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के निष्पादन में और भी काफी सुधार लाता है। ऐसा ही मिर्चाई और ग्रामीण आधारभूत संरचना के अन्य रूपों के लिए भी किया जाना है, जिनकी सीमा और गुणवत्ता उन दशाओं का निर्धारण करती है, जिनमें हमारे तीन-चौथाई नागरिक रहते और कार्य करते हैं।

22. चुनावों के पश्चात् सत्ता में आने वाली सरकार को इन और अन्य चुनौतियों का सामना करना होगा। हमारी ओर से मैं केवल यह कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री, श्री बी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह दिखा दिया है कि उनमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति हेतु आवश्यक कार्यों को करने की इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता है।

23. अब मैं संक्षेप में वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों की चर्चा करूंगा।

24. वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में 172,151 करोड़ रुपए के कुल व्यय का प्रावधान रखा गया था। अब यह व्यय बढ़कर 183,004 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है जो 10,853 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाता है।

25. वर्ष 1995-96 में आयोजना व्यय के लिए, बजट अनुमानों में 48,500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था अब यह व्यय बढ़कर 48,684 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। ग्रामीण विकास क्षेत्र की बढ़ी हुई आवश्यकता तथा वर्ष के दौरान घोषित की गई योजनाओं के लिए व्यवस्था करने के लिए मुझे आवंटनों में कुछ समायोजन करने पड़े हैं। संशोधित अनुमान ग्रामीण विकास के आयोजना व्यय में 551 करोड़ रुपए तथा शिक्षा क्षेत्र में 679 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए, केन्द्रीय सहायता, जिसका अनुमान 19,506 करोड़ रुपए लगाया गया था अब बढ़कर 19,854 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है।

26. आयोजना भिन्न व्यय के क्षेत्र में, मैंने खास और उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता हेतु 1,085 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। मुझे

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, लघु बचत संग्रहणों में उनके हिस्से के रूप में, बढ़े हुए ऋणों के लिए 3,112 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करना पड़ा है जो कि बजट अनुमानों से काफी अधिक है। केन्द्र सरकार के कमचारियों और पेंशन भोगियों को प्रदान की गई अंतिम राशन के कारण चालू वित्त वर्ष में लगभग 1650 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। राज्य सरकारों के ऋणों को बढ़े खाने डालने के लिए 1,010 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। रक्षा संबंधी तैयारी के स्तर को बनाए रखने के लिए, रक्षा व्यय के लिए 1,379 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। हमारी आंतरिक सुरक्षा संबंधी बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए, पुलिस संबंधी व्यय के लिए भी मुझे 266 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करना पड़ा है। बेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 745 करोड़ रुपए के ऋण देने के कारण भी व्यय में वृद्धि हुई है। कुल आयोजना भिन्न व्यय में 10,669 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा है।

27. इस माननीय सदन को एक बार फिर से सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे कर-संबंधी सुधारों में हमें लगातार आशातीत लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस तथ्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों से संबंधित बढ़ती हुए प्राप्तियों के संबंध में देखा जा सकता है। बजट अनुमानों की तुलना में सकल का राजस्व की प्राप्तियां 6,592 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है तथा यह राशि बढ़कर अब 110,354 करोड़ रुपए हो जाएगी। हमारे कर संबंधी सुधारों जिनमें उचित कर संबंधी दरों के साथ-साथ उनका कठोर संचालन और व्यापक विस्तार शामिल है, की नीति को सक्रिय रूप से जारी रखने की आवश्यकता है ताकि हम आने वाले वर्षों में और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। राजस्व विभाग के वे अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं, जिनकी निष्ठा और अथवा प्रयासों से हमें ये उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिली है।

28. कर-भिन्न राजस्व, जो कि हमारी प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है में भी पर्याप्त वृद्धि दिखाई देती है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों की राशि जिसका बजट अनुमानों में 26,413 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, अब संशोधित अनुमानों में बढ़कर 29,103 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कर-भिन्न प्राप्तियों में सेलुलर दूरसंचार सेवाओं के निजी संचालकों से लाईसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त 1,850 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। सामान्य राजस्व में इन प्राप्तियों से, सरकार को उच्च प्राथमिकता वाले विकास संबंधी कार्यों के लिए अधिक संसाधन प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस सदन को यह जानकारी है कि कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय के

निर्णय ने सरकार के पक्ष को उचित ठहराया है तथा बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के लिए लाईसेंस आर्बिट्रेशन करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। फिर भी प्राप्तियों के बारे में समय निर्धारण संबंधी अनिश्चितता के कारण तथा अत्यधिक मावधानी के तोर पर चालू वर्ष में बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के संचालकों से प्राप्त लाईसेंस शुल्क के लिए मैं कोई श्रेय नहीं ले रहा हूँ।

29. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी ईक्विटी के निवेश से गैर-रूढ़न सृजनकारी पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमानों की तुलना में काफी कम होगी, जिसका मुख्य कारण वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान पूँजी बाजार में मंदी की स्थिति रहना है। ये प्राप्ति का अब केवल 357 करोड़ रुपए की होगी जब कि इसकी तुलना में बजट अनुमान 7,000 करोड़ रुपए के थे।

30. प्राप्ति और व्यय में उतार चढ़ाव को देखते हुए चालू वर्ष के अंत तक 7,600 करोड़ रुपए का बजट घाटा होने का अनुमान है। मूल रूप से राजकोषीय घाटा 57,634 करोड़ रुपए होने का अनुमान था जो कि कुल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत था। अब यह घाटा 64,010 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत बैठता है। बजट अनुमानों की तुलना में राजकोषीय घाटे में अधिकांश गिरावट का कारण लघु बचतों का अधिक मात्रा में जुटाया जाना है। लघु बचतों के संग्रहण की राशि में से तीन चौथाई राशि राज्यों को ऋण के रूप में दी गई है। इसलिए, जब लघु बचतों के संग्रहण की राशि बजट अनुमानों से अधिक हो जाती है, तो केन्द्र का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। यदि इस वर्ष लघु बचत संग्रहण बचत स्तर से अधिक न बढ़ते तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5-6 प्रतिशत ही रहता।

31. 1996-97 की कर और व्यय नीतियों पर आते हुए मैं यह स्पष्ट करूँगा कि इसके अन्तर्गत अगले पांच वर्षों में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मध्यावधिक उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। माटे तौर पर यह उद्देश्य इस प्रकार है।

- (क) मूल्यों की उचित स्थिरता के ढाँचे में प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत तक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने वाली स्थूल आर्थिक नीतियों को जारी रखना।
- (ख) ऐसे विकास का प्रतिपास तैयार करना जिससे कि प्रति वर्ष कम से कम 10 मिलियन से अधिक नई नौकरियों की वृद्धि हो।
- (ग) आर्थिक और सामाजिक नीतियों का पुनर्निर्माण करना ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात सन् 2001 तक 10 प्रतिशत से कम हो जाए।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि भारतीय कृषि में प्रति वर्ष कम से कम चार प्रतिशत की वार्षिक दर से विकास होना रहे जिसमें फसल पद्धति के विविधीकरण को बढ़ावा देते तथा शुष्क भूमि की कृषि में उत्पादकता और पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों में वृद्धि करने के विशेष प्रयास का सुधार करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर अधिक बल दिया जा सके।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय उद्योग को और अधिक सुदृढ़ करना तथा प्रति वर्ष लगभग 25 प्रतिशत की दर पर निर्यातों में सतत वृद्धि सुनिश्चित करना।

(च) विकास के स्तरों में क्षेत्रीय असमताओं को तेजी से कम करने पर विशेष बल देने हुए विद्युत यातायात संचार तथा सड़कों की गुणवत्तात्मक आर्थिक आधारभूत संरचना का विस्तार और सुधार करना।

(छ) असुरक्षित वर्गों को अधिक कारगर और प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक सुरक्षा तन्त्र को और मजबूत बनाना तथा उनका विस्तार करना।

(ज) बालिका शिक्षा पर विशेष बल देने हुए और साध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ व्यावसायिक आधार प्रदान करने हुए वर्ष 2001 तक प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित रूप से सर्वसुलभ बनाना।

(झ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के जर्गु प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं का विस्तार करना तथा शिशु मृत्यु दरों में केरल जैसे राज्यों में विद्यमान स्तर तक कमी लाने पर अत्यधिक बल देना।

(ञ) आश्रय स्थल, ग्रामीण आवास की व्यवस्था तथा गन्दी बस्ती सुधार से संबंधित कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत से नए कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। तथापि, संवैधानिक मर्यादा की यह मांग है कि कर और व्यय दोनों की संयुक्त नीतियों वाले ये कार्यक्रम नई सरकार द्वारा तैयार किए जाएं जो कि लोकसभा के आगामी चुनावों के उपरान्त अपना कार्यभार संभालेगी इसलिए 1996-97 के अंतर्गम बजट में कोई नया कार्यक्रम शामिल नहीं है।

32. आगामी बित्त वर्ष के प्रथम 4 महीनों के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को सक्षम बनाने हेतु

लेखानुदान के प्रयोजन के लिए मैं अंतरिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुदान की मांग तथा वार्षिक वित्तीय विवरण पूरे वित्त वर्ष के लिए है तथा नियमित बजट प्रस्तुत करने समय उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा।

33. अब मैं वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों पर आता हूँ। मैं आयोजना व्यय के लिए बजट अनुमानों में वृद्धि करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ। जो वर्ष 1995-96 के अनुमानों में 48,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में 50,521 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आयोजना के लिए प्रस्तावित बजटीय सहायता भी अंतरिम है तथा नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय उसकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता होगी। तथापि, मैं जो राशि प्रदान कर रहा हूँ वह यह सुनिश्चित करेगी कि विकासार्थक कार्यों की गति इसी प्रकार बनी रहे तथा चालू वर्ष के दौरान आरंभ की गई मुख्य सामाजिक क्षेत्र योजनाओं को पूरे वर्ष की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा किया जाए।

34. मैंने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्रों के लिए और अधिक बजटीय सहायता प्रदान की जाए।

—माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना की अवधि के दौरान ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त राशि को अत्यधिक रूप से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था जब कि सातवीं योजना के दौरान इसका वास्तविक व्यय 11,000 करोड़ रुपए का था। 1996-97 के लिए 8,692 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटनों के पश्चात आठवीं योजना के दौरान कुल व्यय 33,400 करोड़ रुपए होगा। यह राशि सातवीं योजना के दौरान किए गए वास्तविक व्यय से तीन गुणा से भी अधिक बैठती है।

—मैंने शिक्षा संबंधी योजना व्यय के लिए लगभग 880 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों की कमी के कारण मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम से 7.2 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचने की आशा है।

—मैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के आवंटन को भी 1995-96 में 550 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1996-97 में 932 करोड़ रुपए कर रहा हूँ।

—मैं इंदिरा आवास योजना के आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि 1996-97 में ग्रामीण निर्धनों के लिए 10 लाख से भी अधिक मकानों की व्यवस्था की जा सके।

—दस लाख कुपोषण (मिलियन वैन स्कैम) के लिए 418 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे गरीबी रेखा से नीचे वाले छोटे तथा सीमान्त किसानों को उनकी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभकारी आस्തിयां प्रदान की जा सकें।

—अक्टूबर 1993 में आरम्भ की गई राजगार राज्य-वामन योजना को बड़ी उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। 1996-97 में इस योजना के लिए 1970 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

35. 1996-97 के दौरान कुल आयोजना भिन्न व्यय 151,503 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 134,320 करोड़ रुपए थी। हमारे आयोजना भिन्न व्यय में भारी मात्रा में वृद्धि का एक मुख्य कारण व्याज संबंधी भार है। चालू वर्ष के 52,000 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 1996-97 में व्याज अदायगियों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखे जाने का अनुमान है। व्याज संबंधी अदायगियां मुख्यतः पहले से लिए गए उधारों को प्रदर्शित करती हैं। हाल ही के वर्षों में यदि हम राजकोषीय घाटे को कम करने में सफल नहीं हुए होते तो व्याज की यह राशियां और भी अधिक होती। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि राजकोषीय घाटे को कम करने पर हमारे वन दिए जाने से आने वाले वर्षों में व्याज के भार में कमी आने के रूप में हमें भारी लाभ होगा। राजकोषीय घाटे को और अधिक नियंत्रणीय तथा वृहतीय स्तर तक लाने संबंधी हमारे संकल्प में किसी प्रकार की ढील नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी कर-प्रणाली में निरन्तर सुधार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा और अधिक आंतरिक संसाधन जुटाने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक विनिवेश तथा आर्थिक सहायता को सक्षम-स्तर तक सीमित रखने से उच्च प्राथमिकता वाली विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए संसाधन मुक्त रूप से सुलभ हो जाएंगे।

36. इस अंतरिम बजट में मैं रक्षा के लिए 27,819 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूँ जबकि 1995-96 के बजट अनुमानों में यह राशि 25,500 करोड़ रुपए थी। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रक्षा संबंधी तैयारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा सदन इस बात से आश्वस्त रहे कि हम अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। नियमित बजट तैयार करते समय रक्षा संबंधी प्रावधान में और भी संशोधन किए जाएंगे। मैं खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5,774 करोड़ रुपए तथा उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 6,800 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान कर रहा हूँ। आकस्मिक खर्चों के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा के आम चुनाव कराने के लिए भी 400 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

37. जहाँ तक प्राप्तियों का संबंध है अंतरिम बजट में कर संबंधी राजस्व के अनुमान कराधान की विद्यमान दरों के अनुसार तैयार किए गए हैं। कराधान की विद्यमान दरों के अनुसार सकल कर राजस्व 128,540 करोड़ रुपए बैठता है। अगर वर्ष, करों में राज्यों का हिस्सा 34,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 29,266 करोड़ रुपए है। परिपक्वता देयता को ध्यान में रखते हुए 1996-97 में लघु बचन संग्रहणों की निबल राशि 15,716 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मैं अगले वर्ष और स्फीतिकारी संसाधन जुटाने की नीति को जारी रखते हुए विनिवेश से प्राप्तियों के रूप में 5,000 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूँ। मुझे लाभार्थों में भी वृद्धि होने की आशा है तथा 1996-97 में इन प्राप्तियों की राशि 4,051 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

38. प्राप्तियों और व्यय में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, कराधान की वर्तमान दरों के अनुसार केन्द्र की कुल निबल राजस्व प्राप्तियाँ 127,162 करोड़ रुपए तथा कुल व्यय 202,024 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 1996-97 के दौरान बजटीय घाटा 5,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा राजकोषीय घाटा 62,404 करोड़ रुपए होने की संभावना है। अंतरिम बजट में दिए गए मेरे प्रस्तावों से राजकोषीय घाटे को और अधिक नियंत्रणीय अनुपातों तक कम करने की दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि इन अनुमानों के आधार पर, 1996-97 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत होगा। मैं इसमें और सुधार करना चाहता था। मुझे अपने प्रयासों को सीमित रखना पड़ रहा है क्योंकि इस समय में अंतरिम बजट पेश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं मेरे इन प्रयासों में इस दिशा में किए जाने वाले अभिवृद्धित प्रयासों के लिए ठोस आधार मिलेगा।

39. मैं एक त्रित विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखता हूँ जिसमें वित्तीय वर्ष 1996-97 में आयकर की वर्तमान दरों को जारी रखने की मांग की गई है। मैं सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ।

40. अत्यन्त महोदय मैंने हमारी उपलब्धियों, किए जाने वाले अग्रदूत रह गए कार्यों और साथ ही युद्ध, गरीबी तथा शोषण के भय से मुक्त भारत, एक ऐसा भारत जो एक मजबूत आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था निर्मित करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाए; एक ऐसा भारत जो कानून के शासन और मौलिक मानव स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास पर आधारित एक मुक्त समाज और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के ढाँचे में उत्कृष्टता और सामाजिक समानता के दोहरे प्रयास के लिए दृढ़तापूर्वक बचनबद्ध हो; के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य की

प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले भावी आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों की दूरदृष्टि का उल्लेख करने का प्रयास किया है।

41. विनांक, 24 जुलाई, 1991 को इस माननीय सदन में अपने प्रथम बजट भाषण में मैंने विक्टर ह्यूगो का उद्धरण देते हुए कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसके आधिभाँव का समय आ गया हो। मैंने इस सदन को यह भी सुझाव दिया था कि विश्व अर्थव्यवस्था के आर्थिक शक्ति में केन्द्र में भारत का अग्रणी रूप से उभरना भी एक ऐसा विचार था, जिसका वास्तव में उपयुक्त समय आ गया था। कड़ी चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद, इस स्वप्न को साकार रूप देने में हमने भरपूर परिश्रम किया है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा पहले से ही छठा स्थान है। हम इस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। लेकिन इसके लिए हमें दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिक नेतृत्व; निरंतर कठोर परिश्रम, तथा हमारे राष्ट्रीय जीवन में कड़ा अनुशासन अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होगी। हम अपने राष्ट्र की व्यापक शक्ति को बेतुके साम्प्रदायिक भेदभाव अथवा जाति और संघर्ष में व्यर्थ नहीं गंवा सकते और न ही हम अल्पदृश्यता की शक्तियों को स्वदेशी के लिए राष्ट्रीय बचनबद्धता को आर्थिक पिछड़ेपन को जारी रखने और भारत को विश्व में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने से रोकने के लिए सफल होने देंगे। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने हमें सिखलाया था कि पारस्परिक निर्भरता वाले विश्व में स्वदेशी का तात्पर्य आर्थिक अकेलापन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता वाले एक ऐसे समृद्ध भारत का निर्माण करना है, जो विश्व में अन्य देशों के साथ बराबरी से कार्य कर सके। हम एक ऐसे नवीन भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो कि, गांधी जी के शब्दों में, एक ऐसे घर की तरह होगा जिसकी खिड़कियाँ सभी दिशाओं में खुली हों; विश्व की सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं की विचारधाराओं को स्वच्छन्दतापूर्वक अन्दर आने दें, लेकिन उनमें से किसी भी विचार धारा के कारण हमारे पांव उखड़ें नहीं। स्वदेशी का यही सच्चा सार है और हम इस मूल सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।

42. भारत शानदार नए अवसरों की दहलीज पर खड़ा है। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि भारत की मुख्य कमी इसकी अत्यधिक गरीबी और अज्ञानता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल ही की उपलब्धियों को धन्यवाद देना होगा जिसके कारण अब हम गरीबी, अज्ञानता और बीमारी का पहलू की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। स्वामी विवेकानन्द, महत्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहर लाल नेहरू की उच्च विचारधाराओं तथा मानवतावाद

से प्रेरणा लेकर हमारी पार्टी और हमारी सरकार इस महान राष्ट्रीय कार्य को सफलतापूर्वक आगे नढ़ाने के संकल्प को पुनः दोहराती है। हम इसमें विजयी होंगे।

43. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान लोकसभा का यह आखिरी सत्र है। शीघ्र ही हमारी जनता को अपने मार्क्समार्क प्रजातान्त्रिक अधिकार का प्रयोग करने अर्थात् हमारी सरकार चुनने के लिए कहा जाएगा। निस्सन्देह उनके चयन का हमारी शासन प्रणाली के भविष्य पर तथा हमारे बच्चों के कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हर बार भारतीय जनता ने दिखा दिया है कि श्रद्धा और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए उन पर विश्वास किया जा सकता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब समय आएगा तो हमारी जनता दायिनी बाने उस हाथ को पहचान लेगी, जो आदि और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने तथा अपनी एकता और निष्ठा को बनाए रखने में हमारे राष्ट्र की सहायता कर सकता है।

सी.एम. वामुदेव, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1996

No. F. 15(59)-B(D)/95.—The following is published for general information :—

Budget 1996-97

(Interim)

Speech of

Shri Manmohan Singh

Minister of Finance

28th February, 1996

Mr. Speaker Sir,

I rise to present the Interim Budget for 1996-97.

2. Five years ago, the people of India gave a mandate to our Party, under the courageous and far sighted leadership of Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao. We took office at a time when the economy was on the brink of collapse. Inflation was out of control, exports were declining, foreign exchange reserves had declined to no more than two weeks' imports and industry was virtually crippled. We had to give the highest priority to restoring macroeconomic stability and then, as quickly as possible, bring the economy back to a path of rapid and equitable economic growth.

3. The strategy we have followed has been outlined before this House by the Prime Minister himself on several occasions. We have sought to accelerate the rate of growth of our economy and achieve broad based development, which alone can ensure a rising standard of living for all our people. We have sought to modernise our economy, improve productivity and increase efficiency in all sectors. We have sought to integrate our economy more effectively with the world, so that we can compete successfully in world markets and also attract larger volumes of investment, as so many other countries in Asia have done to their advantage. Above all, we have sought to ensure that in this process the needs

of the poorer sections of our society are constantly kept in view. As the private sector has expanded vigorously into many areas which were earlier reserved for the State, the focus of State activity and the deployment of public resources is now being concentrated on meeting the needs of the poor and on the social sectors such as health, education and rural infrastructure where the market economy alone cannot bring benefits rapidly.

4. The journey of the past five years has been both difficult and rewarding. I would not say that we have achieved all that we wanted. But, I believe we can honestly say that the results we have achieved amply vindicate our approach and aspirations. Let me briefly review the progress in some important areas.

5. Inflation is our worst enemy and it hurts the poor more than anyone else. Control of Inflation was therefore our first priority. We worked hard to achieve this objective by reducing the fiscal deficit, curbing the growth of money supply and increasing the supply of essential commodities. The result is evident. The annual rate of inflation was as high as 17 per cent in August 1991. It has been brought below 5 per cent in February 1996, the lowest level since 1988. Furthermore, the annual rate of price increase of essential commodities such as wheat, edible oils and sugar, is even lower. To mitigate the impact of inflation on the poorer sections, the Public Distribution System has been strengthened. The revamped PDS has been extended to 1775 blocks in tribal, hilly, desert and other remote areas. A further expansion of RPDS to more than 650 additional blocks is in process.

6. Our policies have also produced a resurgence of economic growth. After slumping to less than one per cent in the crisis year of 1991-92, the rate of growth of Gross Domestic Product rebounded to 5 per cent per annum in both 1992-93 and 1993-94. It then accelerated to 6.3 per cent in 1994-95 and continued high growth of 6.2 per cent is estimated for 1995-96. By any standards this has been one of the swiftest and strongest recoveries from a serious macroeconomic crisis in the entire world. In the first four years of the Eighth Plan, growth has averaged 5.7 per cent. This is in line with the Plan target of 5.6 per cent.

7. This exceptional recovery has been under-pinned by strong performance of all major sectors of the economy. Agriculture provides livelihood for two-thirds of our people and has been given high priority in our policies. We have provided more remunerative prices. We have removed barriers to internal and external trade in agricultural commodities. We have encouraged agro-processing activities. We have sharply reduced the bias against agriculture in our foreign trade policies. The goal has been to quickly expand income earning opportunities for our farmers.

8. Honorable Members will join me in paying handsome tribute to our farmers. They have responded superbly to these new policies. Agricultural production declined during the crisis of 1991-92 but thereafter it has grown by more than 4 per cent per year, on average, in the next three years. Food production also rose by more than 4 per cent per year, on average, to reach a record level of 191 million tonnes in 1994-95. A similar bumper output is expected in 1995-96. Foodgrain production, however, is only one part of the story. Agriculture has also diversified. Milk production has gone up by nearly 10 lakh tonnes between 1990-91 and 1994-95. The production of fruits and vegetables has also increased substantially.

9. So much for those critics who used to claim that our policies have neglected agriculture.

10. Our industry has responded magnificently to the stimulus of our policies of unshackling domestic industry and to the challenge of international competition. Many had predicted that the liberalisation of imports would swamp domestic industry. We had more confidence in our industry. Five years ago I had said that "our entrepreneurs are second to none". They have amply vindicated the faith we placed in them. Industrial production was stagnant in 1991-92. It recovered robustly to grow by 6 per cent in 1993-94 and then further increased to 8.6 per cent in 1994-95. Industrial growth has accelerated to 12 per cent in the first half of 1995-96. Capital goods production surged in 1994-95 by 25 per cent. This is more than twice the growth recorded by the other broad categories of basic goods, intermediate goods

and consumer goods. The capital goods sector continued to outpace the other sectors in the first half of 1995-96, recording a growth of 14.3 per cent. This has happened despite the opening up of the economy to competition from imports. None can now doubt the inherent strength and competitiveness of our industry.

11. I am particularly happy to inform Honourable Members that our reform policies have given a special boost to small scale industry. In each year after the crisis, the production from small scale industry has grown faster than overall industrial production. For example, in 1993-94 output of small scale industry rose by 7.1 per cent, whereas overall industrial production grew by 6.0 per cent. Similarly, in 1994-95 small scale industrial growth of 10.1 per cent outpaced overall industrial growth of 8.6 per cent.

12. As I have already mentioned our strategy of reform accorded the highest priority to improving the living standards of the poor. We have pursued a three-pronged approach of promoting rapid, broadbased employment-generating growth, broadening and deepening special programmes for poverty alleviation and employment generation and giving a strong thrust to programmes for social sectors and social security. In 1991 our critics had warned that economic reforms would lead to massive unemployment and the poor would bear the brunt of adjustment. The results show that these fears were misplaced.

- * The total increase in employment in the economy was 3 million in 1991-92. It doubled to an average of 6 million in the next two years and exceeded 7 million in 1994-95. Employment growth is likely to be even higher this year. This compares with an average increase of less than 5 million per year in the eighties.
- * The latest Planning Commission estimates of poverty show a significant decline in the proportion of people below the poverty line. The proportion fell from above 25 per cent in 1987-88 to below 19 per cent in 1993-94.
- * The average real wage for unskilled agricultural labour, one of the weakest sections of our society, also shows improvement. Real wages fell by 6 per cent in the crisis year of 1991-92. Thereafter they rose steadily at an annual rate of 5 per cent in each of the next three years.

13. Despite tight fiscal constraints, we have, in the three years between 1992-93 and 1995-96, increased the Central Plan budget allocation for rural development by about 150 per cent, for education by over 90 per cent, for elementary education by nearly 130 per cent and for health by over 120 per cent. We have launched important new programmes and initiatives for the weaker sections.

- * The Employment Assurance Scheme provides assured employment for 100 days to unskilled rural poor at the rate of two persons per family in 3175 poorest blocks of the country during the lean season.
- * The Prime Minister's Rozgar Yojana is designed to generate employment through setting up micro enterprises by educated unemployed. In 1994-95, 1.9 lakh beneficiaries were sanctioned loans under the scheme. The target for 1995-96 is 2.6 lakh beneficiaries.
- * The National Social Assistant Programme has three key components. The first provides monthly old age pension from the Central Government of 75 rupees to those below the poverty line. This is expected to benefit 54 lakh people. Second, there is a lump-sum survivor benefit on the death of the primary bread winner in poor households of 10,000 rupees in the case of accidental death and 5,000 rupees in the case of death from natural causes. This is expected to benefit 4.5 lakh families a year. Third, there is a maternity benefit of 300 rupees for expectant mothers. This is anticipated to benefit 46 lakh women each year.

- * The Mid-day Meal Programme is intended to improve nutrition and school attendance of 11 crore children in classes I to IV in 3 years. In the first year of the scheme 3.4 crore children have already been covered.
- * Under the Indira Awas Yojana 4 lakh houses were built for poor families in rural areas in 1994-95. 10 lakh houses will be built under the Scheme in 1995-96.
- * The Mahila Samridhi Yojana aims at empowering women through giving them greater control over household savings.
- * The Rural Infrastructural Development Fund has been established in NABARD. It will provide Rs. 2,000 crore for completing ongoing projects of medium and minor irrigation, soil conservation and other rural infrastructure.
- * Bank credit for village and khadi industries is being expanded through the provision of a special bank consortium fund of Rs. 1,000 crore.
- * A new Group Life Insurance Scheme of the LIC to provide life cover of 5,000 rupees to each person is being implemented by Panchayats in rural areas, with a subsidized premium for poor households.
- * The National Backward Classes Finance and Development Corporation, which we set up in 1992, has sanctioned over Rs. 250 crore of loans to beneficiaries.
- * The National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation has sanctioned loans of Rs. 400 crore.
- * The National Minorities Development and Finance Corporation for assisting development of backward sections among minorities has become operational.
- * The Handicapped Development and Finance Corporation is being established with authorised capital of Rs. 400 crore.

14. We are proud of the role played by the Indian workers in accelerating the pace of industrial development. A number of steps have been taken to protect and promote their interests. We have raised the eligibility limit for payment of bonus from Rs. 2,500 to Rs. 3,500 per month and the ceiling for calculation of bonus from Rs. 1,600 to Rs. 2,500 per month. Earlier, Government had increased the ceiling under the Payment of Gratuity Act to enable workers to get gratuity up to Rs. 1 lakh. The revised ceilings for bonus eligibility and bonus calculation are applicable to both non-government and to government employees. We gave one instalment of interim Relief to government employees even before the establishment of the Fifth Central Pay Commission. A second instalment was given subsequently on the basis of an interim report of the Pay Commission. Interim Relief has also been given to pensioners and family pensioners. We have also merged a portion of Dearness Allowance with pay for calculating gratuity.

15. History was made with the passage of the Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992, which made it a constitutional requirement to set up in every State, Panchayats at the village intermediate and district levels. The Amendment ensures that women and other weaker sections of the society will necessarily get adequate representation in the Panchayats. This is a major step forward for the empowerment of these under-privileged sections of the society. To make this devolution of power a reality, each State is required to set up a Finance Commission to recommend the principles which should govern the distribution of the State revenue between the State and the Panchayats. The Tenth Finance Commission has also allocated a sum of about Rs. 4,400 crore to be given to the Panchayati Raj Institutions over the next four years.

16. The crisis of 1991 was most visibly reflected in our balance of payments. In the past five years, our foreign trade and external payments policies have transformed weakness into strength.

- * Exports declined in dollar value in 1991-92. They grew by 20 per cent in 1993-94, and by 18 per cent in 1994-95. Export growth has accelerated to 24 per cent in the first 9 months of 1995-96.
- * Trade liberalization has actually increased our self-reliance in foreign trade. The ratio of export earnings to import payments has risen from an average of 60 per cent in the eighties to 90 per cent in the last two years.
- * Foreign investment has risen from less than 260 million dollars in 1991-92 to nearly 5 billion dollars last year. Direct foreign investment flows are expected to rise to about 2 billion dollars this year. Honourable Members will be happy to hear that over 85 per cent of foreign investment approvals are in the priority sectors, including infrastructure and more than 80 per cent of proposals involve joint ventures with Indian companies.
- * On the eve of the 1991 crisis, our external debt was rising at 8 billion dollars per year. In the four and half years from April 1991 to September 1995, the growth of external debt has averaged only 2.2 billion dollars per year. The ratio of external debt to GDP has fallen from a peak of 41 per cent in 1991-92 to about 29 per cent in September 1995. Correspondingly, debt service payments, as per cent of current earnings, are likely to drop from above 35 per cent in 1990-91 to below 27 per cent in 1995-96. Furthermore, the proportion of short-term external debt has been brought down from above 10 per cent in March 1991 to below 5 per cent in September 1995.

17. As part of the economic reforms, we have undertaken sweeping measures to strengthen our banking system and capital markets. As a result, the number of public sector banks declaring operating losses has fallen dramatically from 8 in 1992-93 to only one in 1994-95. The average ratio of non-performing assets to total advances of public sector banks has also declined significantly from 26 per cent in 1992-93 to 20 per cent in 1994-95. An ambitious programme for rehabilitation and restructuring of Regional Rural Banks has been launched.

18. Our programme of capital market reform has greatly increased the mobilization of investible funds through primary issues from about Rs. 6,000 crore in 1991-92 to over Rs. 27,500 crore in 1994-95. Even more important, we have strengthened regulation and supervision over the capital markets with a view to improving the transparency, efficiency and integrity of our stock exchanges. Systematic and determined efforts have been made to modernize the infrastructure and working of capital markets. In 1992 the National Stock Exchange did not exist. By 1995, this modern, computerized and screen-based exchange, which sets new standards of transparency in trading, accounted for more trading volume than any other stock exchange in the country. We have also taken steps to establish a system of depositories which will greatly improve our settlement systems.

19. Our reforms in the financial sector designed to promote savings and investment in our economy. As I have stated earlier, we must rely more and more on our own resources to finance the process of development. I am happy to report to this august House that our thrust towards self-reliance has met with success. Last year our rate of gross domestic savings (as a ratio to GDP) set a new record of 24.4 per cent, higher than at any time in our history. This financed a high rate of gross domestic investment 25.2 per cent of GDP, and supported a record high level of real gross fixed investment, at 22.2 per cent of GDP.

20. To summarize, Mr. Speaker Sir, our economy today is growing faster than 6 per cent per year. Industry is growing rapidly. Agricultural production is strong. Foodstocks are high. Employment growth is buoyant. Poverty is declining. Inflation is at its lowest ebb in many years. Exports are booming. Foreign investment is buoyant. Foreign exchange reserves are comfortable. And the level of savings and investment is high.

21. These are all impressive economic achievements. They are the direct result of the political leadership and vision of the Prime Minister in bringing about an evolution in our policies which has enabled our workers and our farmers, our entrepreneurs and our managers, our scientists and other professionals to demonstrate their inherent potential. The dynamism that has been unleashed augurs well for the future. And yet, the tasks of economic reform are by no means over. Whichever government comes to power after the elections, will face the challenge of maintaining and improving on the strong record of economic performance of the past few years. The task will not be easy. A further reduction in the fiscal deficit will be essential to keep inflation low, reduce interest rates and prevent pressure on the balance of payments. We have begun the process of inducing private investment into key infrastructure sectors such as power, telecommunications, petroleum roads and ports. There has already been strong response to our initiatives in the power and telecommunications sectors and private investment in roads, bridges and ports has also begun. But we will need to build on these initiatives and undertake further reforms of the policy framework for key infrastructure sectors to ensure high levels of public and private investment, efficient operation and expanded provision of reliable services, in adequate supplies and at affordable prices. Systematic reforms will have to be pursued in power, coal, petroleum, roads and ports, if the current buoyancy in economic growth, employment and exports is to be sustained. Further reforms in trade and industrial policy are necessary. Restructuring and reform of public enterprises must be pursued with vigour. Our system of industrial relations also needs reform. The performance of our social sectors, especially primary education and health, has to improve further substantially. The same goes for irrigation and other forms of rural infrastructure whose extent and quality determine the conditions within which three-quarters of our citizens live and work.

22. These and other challenges will face the Government which will take office after the elections. On our part I can only say that our Government, under the leadership of Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao, has shown that it has the will and vision to face the challenges ahead and do what is necessary for India's economic and social progress to forgo ahead.

23. I shall now briefly go over the Revised Estimates for 1995-96.

24. Budget Estimates for 1995-96 had placed the total expenditure at Rs. 172,151 crore. This is now expected to go up to Rs. 183,004 crore, showing an increase of Rs. 10,853 crore.

25. Plan expenditure in the year 1995-96 was estimated at Rs. 48,500 crore in the Budget Estimates. It is now expected to go up to Rs. 48,684 crore. To provide for the increased requirement of rural development sector and for schemes announced during the year, I have had to make some adjustments in allocations. The revised estimates show an increase of Rs. 551 crore for Plan expenditure in rural development and an increase of Rs. 679 crore in education. Central assistance to State and U.T. Plans, which was estimated at Rs. 19,506 crore is now expected to increase to Rs. 19,854 crore.

26. On the non-Plan side I have provided for an additional sum of Rs. 1,085 crore on account of food and fertilizer subsidies. I have also had to make provision for Rs. 3,112 crore for increased loans to States and Union Territories as their share in small savings collections, which have far exceeded budget expectations. The Interim Relief granted to the Central Government employees and pensioners will result in additional expenditure estimated at about Rs. 1,650 crore in the current financial year. A sum of Rs. 1,010 crore has been provided as write off of loans of State Governments. An additional sum of Rs. 1,379 crore has been provided for defence expenditure to keep up the level of defence preparedness. I have also had to provide an additional Rs. 266 crore for expenditure on police in keeping with our heightened internal security requirements. There has also been an increase in expenditure of Rs. 745 crore on account of loans to public sector enterprises mainly for payments of salaries and wages. Total non-Plan expenditure has entailed an additional provision of Rs. 10,669 crore.

27. I am happy once again to report to this august House that our tax reforms have continued to yield benefits beyond our expectations. This is shown by the much higher receipts both in direct and indirect taxes. Gross tax revenues are now expected to exceed budget estimates by Rs. 6,592 crore and reach Rs. 110,354 crore. Our strategy of tax reforms, consisting of moderate rates but tighter administration and expanded coverage, will need to be actively pursued so that we are able to get even higher returns in the years to come. Officers of the Revenue Department, whose dedication and untiring efforts have helped in achieving these exemplary results, deserve commendation.

28. Non-tax revenues, which constitute an important component of our receipts, have also shown healthy buoyancy. Receipts under this head, which were estimated at Rs. 26,413 crore in the Budget, are now expected to be Rs. 29,103 crore in the revised estimates. I am glad to inform the House that non-tax receipts include Rs. 1,850 crore as licence fee from the private operators of cellular telecom services. These receipts to General Revenues will enable the Government to provide larger resources for high priority development activities. The House is aware that the Supreme Court judgement a few days ago has vindicated the Government's stand and cleared the way for allocation of licences for basic telecom services. However, because of some uncertainty with regard to timing of receipts and as a matter of abundant caution, I am not taking credit for licence fees from operators of basic telecom services during the current year.

29. Non-debt creating capital receipts from disinvestment of government equity in public sector undertakings will be much lower than budgeted, mainly because of somewhat depressed conditions in capital markets for much of the year. These receipts will only amount to Rs. 357 crore as compared to budget expectations of Rs. 7,000 crore.

30. Taking into account the variations in receipts and expenditures, the current year is expected to end with a budget deficit of Rs. 7,600 crore. The fiscal deficit was originally budgeted at Rs. 57,634 crore and placed at 5.5 per cent of GDP. It is now expected to be Rs. 64,010 crore. This amounts to 5.9 per cent of GDP. Most of the deterioration in the fiscal deficit compared with the budget estimates is due to the increased mobilisation from small savings. Three quarters of small savings collections are on-lent to the States. Therefore, when small savings collections exceed budget estimates, the Centre's fiscal deficit increases. If small savings collections this year had not exceeded the budgeted level, the fiscal deficit would have been only 5.6 per cent of GDP.

31. Coming to the tax and expenditure policies for 1996-97, these must take into account the medium term objectives for accelerated economic and social development in the next five years. Broadly stated, these objectives are :

- (a) To pursue macroeconomic policies seeking to accelerate the rate of economic growth to 7 to 8 per cent per annum in a framework of reasonable price stability.
- (b) To design a pattern of growth which would lead to an annual increase of over 10 million new jobs.
- (c) To refashion economic and social policies to reduce the proportion of people living below the poverty line to less than 10 per cent by 2001.

- (d) To ensure that Indian agriculture continues to grow at an annual rate of at least four per cent per annum, with strong emphasis on the use of modern science and technology to promote diversification of cropping pattern and special efforts to increase the productivity of dry land agriculture and ecologically fragile regions.
- (e) To further strengthen Indian industry to meet the challenge of international competition and ensure sustained growth of exports of about 25 per cent per year.
- (f) To expand and improve the quality of economic infrastructure of power, transport, communications and roads, laying particular emphasis on speedy reduction of regional imbalances in levels of development.
- (g) To strengthen and expand social safety nets to provide more effective and direct assistance to vulnerable sections.
- (h) To ensure universal access to elementary education by the year 2001, laying particular emphasis on the girl child and imparting a strong vocational bias to secondary education.
- (i) To expand primary health care facilities through a programme of national health insurance for those below the poverty line and with strong emphasis on reduction in infant mortality rates to the levels prevailing in States like Kerala.
- (j) To expand substantially the programmes relating to provision of shelter, rural housing and slum improvement.

The realisation of these objectives will require many new programmes. However, constitutional propriety demands that these programmes, involving a mix of both tax and expenditure policies, are worked out by the government which will come into office after the forthcoming elections to the Lok Sabha. To interim Budget for 1996-97 therefore does not include any new programmes.

32. I am presenting an interim Budget for the purpose of a Vote-on-Account to enable the Government to meet expenditure during the first 4 months of the next financial year. The Demands for Grants and the Annual Financial Statement, which are for the entire financial year, would be revised as necessary at the time of presentation of the regular budget.

33. I now turn to the budget estimates for 1996-97. I am proposing an increase in the estimates for Plan expenditure from Rs. 48,500 crore in BE 1995-96 to Rs. 50,521 crore in BE 1996-97. The budget support proposed for the Plan is interim and will need to be reviewed at the time of the regular budget exercise. However the amount I am now providing will ensure that the tempo of development activities is maintained and the full year requirements of major social sector schemes launched during the course of the current year are fully provided for.

34. I have tried to ensure that increased budgetary support is provided for rural development and social sectors.

- * Members may recall that in keeping with the priorities of our Government the outlay for rural development programmes during the Eighth Plan period was stepped up substantially to the level of Rs. 30,000 crore from the actual expenditure of Rs. 11,000 crore during Seventh Plan. With the proposed allocation of Rs. 8,692 crore for 1996-97, the total expenditure during the Eighth Plan will be of the order of Rs. 33,400 crore. This amounts to a more than three-fold increase over the actual expenditure during the Seventh Plan.
- * I have proposed to provide an increase in budgetary support of about Rs. 880 crore for Plan expenditure in education to ensure that implementation of the Mid-Day Meal Scheme does not in any way suffer on account of resources. 7.2 crore children are expected to benefit from this programme in 1996-97.
- * I am also raising the allocation for the National Social Assistance Programme from Rs. 550 crore in 1995-96 to Rs. 932 crore in 1996-97.
- * I propose to increase the allocation for Indira Awas Yojana so that more than 10 lakh houses are provided for the rural poor in 1996-97.
- * A provision of Rs. 448 crore has been made for the Million Well Scheme so that small and marginal farmers who are below the poverty line are provided with remunerative assets for meeting their water needs.
- * The Employment Assurance Scheme which was launched in October, 1993, has elicited heartening response. A provision of Rs. 1,970 crore has been made for this scheme during 1996-97.

35. The total non-Plan expenditure during 1996-97 is estimated to be Rs. 151,503 crore compared to Rs. 134,320 crore in revised estimates for the current year. A major factor which has been contributing to the sizeable increase in our non-Plan expenditure is the interest burden. The provision for interest payments during 1996-97 is estimated to be Rs. 60,000 crore as against Rs. 52,000 crore in the current year. Interest payments represent mainly the legacy of past borrowings. Indeed, they would have been even higher but for our success in reducing the fiscal deficit in recent years. Members will appreciate that our emphasis on reducing the fiscal deficit will pay rich dividends in the form of reduction of interest burden in the years to come. There should be no slackening in our resolve to bring the fiscal deficit to a more manageable and affordable level. This together with continued reforms of our tax system, generation of more internal resources by public sector enterprises, greater disinvestment in public sector enterprises and containing subsidies to affordable levels will free resources for higher priority development needs.

36. I am providing Rs. 27,819 crore for defence in this Interim Budget as against Rs. 25,500 crore in the budget estimates for 1995-96. Defence preparedness is vital for our national security and the House can rest assured that we will not compromise with our country's security. The provision for

defence will be further revised at the time of preparation of the regular budget. I am also providing Rs. 5,774 crore for food subsidy and Rs. 6,800 crore for fertilizer subsidy. An amount of Rs. 5,000 crore is being provided to meet contingent expenditure. A sum of Rs. 400 crore has also been provided for the conduct of general elections to the Lok Sabha.

37. Coming to receipts, the estimates of tax revenues have been made at existing rates of taxation in the interim Budget. Gross tax revenue at existing levels of taxation is placed at Rs. 128,540 crore. States' share of taxes next year is estimated at Rs. 34,027 compared to Rs. 29,266 crore in the revised estimates of the current year. Taking into account the maturing liability, the net small savings collections are placed at Rs. 15,716 crore in 1996-97. I am taking a credit of Rs. 5,000 crore next year as receipts from disinvestments as continuation of the policy of mobilising non-inflationary resources. I am also expecting an increase in dividends and have estimated these receipts at Rs. 4,051 crore in 1996-97.

38. Taking into account the changes in receipts and expenditure, total net revenue receipts of the Centre, at the existing rates of taxation, are estimated at Rs. 127,162 crore and total expenditure is estimated at Rs. 202,024 crore. The budget deficit during 1996-97 is estimated to be Rs. 5,000 crore and the fiscal deficit is estimated to be Rs. 62,404 crore. My proposals in the interim Budget will take us further in the direction of bringing down the fiscal deficit to more manageable proportions. I expect that on the basis of these estimates the fiscal deficit during 1996-97 will be 5 per cent of GDP. I would have liked to do better. I am restrained in my efforts because I am presenting an interim Budget at this stage. But I am sure that these efforts will provide a sound foundation for enhanced efforts in this direction.

39. I propose to introduce a Finance Bill which seeks to continue the existing rates of Income Tax in the financial year 1996-97. I am not proposing any changes in the rates of Custom and Central Excise duties.

40. Mr. Speaker, Sir, I have sought to outline our achievements, the unfinished task that lies ahead, as well as our vision of the future economic and social agenda we must pursue to realize the national goal of an India free from the fear of war, want and exploitation; an India which takes full advantage of modern science and technology to build a strong, self-reliant and internationally competitive economy; an India firmly committed to the twin pursuit of excellence and social equity in the framework of an open society and democratic polity based on the rule of law and abiding faith in fundamental human freedoms.

41. In my first budget speech to this Honourable House on 24th July 1991, I had stated, quoting Victor Hugo, that no power on earth could stop an idea whose time had come. I had also suggested to this House that the emergence of India as a front ranking economic power house of the world economy happened to be an idea whose time had indeed come. Despite enormous challenges and difficulties, we have worked earnestly to give concrete shape to this dream. We are already the sixth largest economy of the world. We are determined to further move up this ladder. But this will require far-sighted political leadership, sustained hard work and willingness to accept utmost discipline in our national life. We cannot afford to fritter away the vast energies of our nation in senseless

communal strife or caste and class wars. Nor can we allow the national commitment to Swadeshi to be misused by the forces of obscurantism to perpetuate economic backwardness and prevent India from occupying her rightful place in the world. As Jawahar Lal Nehru taught us, in an interdependent world, Swadeshi must not be interpreted to mean economic isolation but rather self reliance in building a prosperous India which interacts as an equal with other countries in the world. We seek to build a new India which, in the words of Gandhiji, will be like a house with windows open on all sides; let ideas from all the cultures and civilisations of the world freely flow in; but we must refuse to be blown off our feet by any one of them. This is the true essence of Swadeshi and we shall not compromise on this essential principle.

42. India is on the threshold of exciting new opportunities. Gandhiji used to say that the central disease of India is its deep poverty and deeper ignorance. Thanks to recent developments in science and technology, it is now possible as never before to wage a successful war against poverty, ignorance

and disease. Drawing inspiration from the high ideals and humanism of Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Gurudev Rabindranath Tagore and Pandit Jawahar Lal Nehru, our party and Government reaffirm our solemn commitment for successful pursuit of this giant national enterprise. We shall overcome.

43. Mr. Speaker, Sir, this is the last session of the present Lok Sabha. Soon, our people will be called upon to exercise their sovereign democratic right to choose the next Government. Undoubtedly, their choice will have a profound bearing on the future of our polity and the well being of our children and our grand children. Time and again, the Indian People have shown that they can be relied upon to make sound and sensible decisions. I have every reason to believe that when the time comes, our people will be discriminating enough to recognise the friendly hand that alone can help our nation to move forward on the road to peace and prosperity and preserve its unity and integrity.

C. M. VASUDEVA, Addl. Secy. (Budget)

